

1	2	3	4
Madhya Pradesh	21.30	48.17	46.0
Maharashtra	17.00	38.99	35.6
Orissa	24.10	44.11	44.5
Punjab	7.20	12.91	11.2
Rajasthan	19.40	38.99	41.5
Tamil Nadu	20.50	43.88	39.2
Uttar Pradesh	27.20	45.22	41.9
West Bengal	20.70	32.84	30.6
ALL INDIA	20.10	40.12	36.5

* These estimates are from a paper by Shri B.3. Minnas, Shri L.R. Jain and Shri S.D. Tendulkar,

Scheme for Rehabilitation of bonded Labour

6358. SHRI SUSHILKUMAR SAMB-
HAJIRAO SHINDE: SMT.
MEENA VERMA-
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether a Rs. 10 crore Centrally sponsored scheme for the rehabilitation of bonded labour has been drawn out for implementation under the Eighth Five Year Plan;

(b) if so, the salient features of the scheme; and

(c) the progress made so far in the implementation thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) An amount of Rs. 4 crores (revised) has been earmarked for the Centrally sponsored scheme for the Rehabilitation of Bonded Labour under the Eighth Five Year Plan.

In order to supplement the efforts of the State Governments. Central Financial assistance on matching grant (50:50) basis upto a ceiling limit of Rs. 6250 per head is provided for the rehabilitation of identified and released bonded labourers. The pattern of assistance is land-based, non-land based or skill/craft based depending upon the aptitude and preference of the beneficiary.

An amount of Rs. 337.54 lakhs has been released to State Governments as Central share of assistance under the Centrally sponsored scheme during 1992-93 and 1993-94.

सिर्फ 1.5 प्रतिशत भारतीयों द्वारा प्रदेश के 75 प्रतिशत संसाधनों का उपयोग

6359. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

श्रीमती सुवमा स्वराज :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1994 के दैनिक समाचार पत्र "पायनियर" में "1.5 प्रतिशत इंडियन्स यूज 75 प्रतिशत रिसोर्सिज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में मात्र 15 प्रतिशत जनसंख्या देश में उपलब्ध सुविधाओं की 75 प्रतिशत भाग को उपयोग में ला रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमानी) (क) से (ग) जी, हां। भारत में घरेलू खपत व्यय के पैटर्न संबंधी विस्तृत आंकड़े सांख्यिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन० एस० एस० ओ०) द्वारा किए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी सर्वेक्षण से उपलब्ध होते हैं। देश में उपलब्ध सुविधाओं का

समग्र उपयोग खपत व्यय के समग्र स्तर में परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन आंकड़ों पर आधारित दशमकवार खपत व्यय वृद्धि वाली एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1987-88 में ग्रामीण क्षेत्रों में खपत व्यय के 75 प्रतिशत में 90 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या भागीदार रही थी तथा शहरी क्षेत्रों में खपत व्यय के 71 प्रतिशत में शहरी जनसंख्या के 90 प्रतिशत ने हिस्सेदारी की थी। अतः यह अनुमान नहीं नहीं है कि 1.5 प्रतिशत भारतीय 75 प्रतिशत संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं।

विवरण

खपत व्यय में जनसंख्या के दशमकों का हिस्सा

जनसंख्या का दशमक	कुल खपत व्यय में दशमक-वार प्रतिशतता हिस्सा							
	ग्रामीण				शहरी			
(उपभोक्ता व्यय के स्तरों के अनुसार)	1973-74	1977-78	1983	1987-88	1973-74	1977-78	1983	1987-88
प्रथम दशमक	3.95	3.46	3.79	4.00	3.90	3.20	3.38	3.38
द्वितीय दशमक	5.61	4.90	5.22	5.33	5.27	4.54	4.63	4.58
तीसरा दशमक	6.33	5.90	6.20	6.24	5.89	5.44	5.49	5.37
चौथा दशमक	7.09	6.50	6.88	6.94	7.03	6.25	6.66	6.12
पांचवां दशमक	8.02	7.52	8.00	7.75	7.68	7.14	7.10	7.11
छठा दशमक	8.98	8.28	9.04	8.77	9.21	8.42	8.21	8.25
सातवां दशमक	18.77			9.83	9.33	9.35	10.27	9.58
आठवां दशमक	12.67	11.35	11.67	11.63	12.35	12.48	11.42	11.58
नौवां दशमक	11.37	14.10	14.59	14.23	14.20	14.17	14.98	15.11
दसवां दशमक	22.59	28.39	24.68	25.28	23.14	57.91	87.94	28.92